श्री जयंत सिन्हा ने शुरू किया-स्वयं सहायता समूहों का डिजीटायजेशन प्रोजेक्ट

श्री जयंत सिन्हा, राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार ने झारखंड के रामगढ जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों के पूर्ण डिजीटायजेशन के लिए नाबार्ड प्रोजेक्ट को लॉच किया. नाबार्ड के इस नवोन्मेषी पहल की प्रशंसा करते हुए श्री सिन्हा ने सहर्ष कहा कि रामगढ जैसे दूरदराज इलाके से की गई यह शुरूआत डिजीटल इंडिया बनाने की दिशा में दूर तक सहायक होगा. श्री सिन्हा ने प्रधान मंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के अधिकाधिक समावेशन की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस बात पर संतोष जाहिर किया कि इस प्रोजेक्ट से विकास कार्य में महिलाओं की सहभागिता भी बढेगी.

डॉ हर्ष कुमार भनवाला, अध्यक्ष, नाबार्ड ने कहा कि नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम से जुडे मुद्दे और हिताधिकारियों की कठिनाइयों को हल करने के लिए यह प्रो-एक्टिव कदम उठाया है. इसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और बैंकों के मध्य संबंधों की गुणवत्ता में सुधार, स्वयं सहायता समूहों के समय पर ऋण संयोजन, कम शिक्षित सदस्यों की बहीखाते रखने की समस्याएं और निर्धनों के लिए बने अन्य सरकारी कार्यक्रमों से उसे जोड़ने जैसे मुद्दे शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि डिजीटायजेशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और उनके सदस्यों का बेस डाटा एक सिस्टम में लिया जाएगा और उसमें लघु बचतों, आंतरिक ऋणीकरण और उनकी चुकौतियों सहित वित्तीय लेनदेनों को आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा. डिजीटायजेशन सोफ्टवेअर को 'एप्प' के साथ स्थानीय भाषा में तैयार किया गया है. स्वयं सहायता समूहों और उनके सदस्यों के आंकडों को इनपुट डेवाइस (टेबलेट/मोबाइल हैंडसेट)में डाला जाएगा जिसे एक सुरक्षित एवं समर्पित वेबसाइट www.eshakti.nabard.org में अपलोड किया जाएगा.

प्रोजेक्ट से कई हिताधिकारियों को लाभ पहुंचेगा. यह स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आधार आधारित वित्तीय समावेशन और प्रधान मंत्री जनधन योजना से जोडने में सहायक होगा जिससे व्यापक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचा जा सकेगा. डिजीटायजेशन की इनबिल्ट ग्रेडिंग प्रबंधन सूचना पद्धति से स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी. बैंकों को ऋण मूल्यांकन,संवितरण एवं अनुप्रवर्तन में आसानी होगी. इसके अलावा, इस प्रक्रिया से सामाजिक लाभों के अंतरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के फायदे मिलेंगे और प्रधान मंत्री जनधन योजना में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित होगी. स्वयं सहायता समूह के सदस्य आसान ई-बुक कीपिंग के जरिए अंतिम लाभार्थी बनेंगे. श्री जयंत सिन्हा ने प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर मार्गदर्शन देते हुए कहा कि नाबार्ड को पिछड़े जिलों में ऋण गहनीकरण पर भी एक प्रायोगिक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए. कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण के महत्व को

रेखांकित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय बजट 2015 में दिए रु 15000 करोड के दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि का समीचीन प्रयोग किया जाएगा.

श्री एच.आर.दवे, उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड ने कहा कि नाबार्ड द्वारा जिला संभाव्यता ऋण योजनाओं के अंतर्गत कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के संभावनायुक्त विविध कार्यकलापों को कार्यरूप में परिणित किया जाएगा. नाबार्ड के जिला कार्यालयों को उचित तकनीकी सहायता, बैंकग्राह्य योजनाएं दी जाएंगी जो बैंकों और सेवा प्रदाताओं के बीच सेतु का काम करेगा.
उन्होंने आगे कहा कि रामगढ से शुरू किए गये इस प्रोजेक्ट को भारत के नौ राज्यों तक ले जाया जाएगा. देश में 74 लाख समूह हैं जिनके बैंक खाते हैं. इनमें से 42 लाख समूह ऋण से संबद्ध है. देश में जब भी डिजीटायजेशन का विस्तार होगा तब इन समूहों को लाभ पहुंचेगा.

----------//----------